

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सी० एम० पी० संख्या—104 / 2019

1. हेमा देवी
2. मनोरमा देवी याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, भूमि और राजस्व, झारखण्ड सरकार, राँची
3. आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर डिवीजन, राँची
4. प्रभारी अधिकारी, सर्वेक्षण और निपटान, राँची
5. सोमरा उरांव
6. संतोष उरांव
7. मंगरा उरांव
8. बिरसा उरांव
9. थेपा उरांव विरोधी पक्ष

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ताओं के लिए : मे० अमर कु० सिन्हा एवं सुमित कुमार, अधिवक्तागण
राज्य के लिए : एस०सी० (एल एंड सी) के ए०सी०

03 / 05.04.2019 वर्तमान सी०एम०पी० को डब्ल्य०पी० (सी) सं० 7370 / 2016 की पुनः स्थापन के लिए दायर किया गया है, जो दिनांक 28.03.2018 के आदेश, जिसके द्वारा त्रुटियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का अनुलंघनीय समय की अनुमति दी गई थी, का पालन न करने के कारण दिनांक 11.04.2018 को चूक के वजह से खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और झारखण्ड राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, साथ-ही-साथ वर्तमान सी०एम०पी० में बताए गए कारणों के आलोक में, डब्ल्य०पी० (सी) सं० 7370 / 2016 को पुनः स्थापित किया जाता है, इस शर्त के अधीन कि याचिकाकर्त्ता अधिवक्ता क्लर्क एसोसिएशन वलफेयर फंड, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पक्ष में, 1,000/- रुपये कॉस्ट का भुगतान करेंगे और डब्ल्य०पी० (सी) सं० 7370 / 2016 में बचे हुए त्रुटियों को आज से एक सप्ताह के भीतर दूर कर दिया जाएगा।

सी०एम०पी० को, तदनुसार, पूर्वोक्त शर्तों के साथ अनुमति दी गई छें

(राजेश शेकर, जे०)